▪ संपादकीय

पर मदद जारी रहे

केंद्र सरकार ने भारतीय मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सब्सिडी हटाने के फैसले से सरकार के 700 करोड़ रुपये बचेंगे, जिसे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में ही केंद्र सरकार को 2022 तक चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था। दरअसल मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका हज सब्सिडी को अव्यावहारिक और अनुपयोगी बताते हुए इसे खत्म करने की मांग कर कर रहा था। उसकी दलील थी कि हज एक लंबी प्रक्रिया है जबकि सब्सिडी सिर्फ हवाई किराए के लिए मिलती है। वास्तव में सब्सिडी के नाम पर एयर इंडिया को कारोबार दिया जाता है। हज के लिए मदद ब्रिटिश काल में भी दी जाती थी। लेकिन सब्सिडी का यह स्वरूप इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू किया गया। उस समय तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन होने के साथ ही हवाई ईंधन की कीमत बहुत बढ़ गई थी। 1973 में समुद्री मार्ग से जा रहे हज यात्री एक हादसे का शिकार भी हुए। तब सरकार ने हवाई सब्सिडी की शुरुआत की, ताकि सुरक्षित और किफायती हज यात्रा सुनिश्चित की जा सके। तब से लेकर हाल–हाल तक यह एक सियासी मुद्दा बना हुआ था। प्रश्न उठाया गया कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कोई सरकार समुदाय विशेष के धार्मिक उपक्रम के लिए सहायता कैसे दे सकती है? हालांकि यह कहने वाले यह नहीं देख रहे थे कि सरकार कैलाश मानसरोवर और ननकाना साहिब गुरुद्वारा की यात्रा के लिए भी सब्सिडी देती रही है। हज सब्सिडी हटाने के फैसले के बाद सरकार ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण नहीं सशक्तीकरण करना चाहती है।

हज सब्सिडी हटाने के फैसले के बाद सरकार ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण नहीं सशक्तीकरण करना चाहती है। हमारे संविधान में सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की हितरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए हज सब्सिडी हटाने के फैसले से धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके हिस्से की कोई सहूलियत उनसे वापस ली जा रही है। उम्मीद करें कि हज सब्सिडी के पैसों से सरकार मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की ऐसी ठोस व्यवस्था करेगी, जिससे गरीब लड़कियों को मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा।

हमारे संविधान में सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की हितरक्षा और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए हज सब्सिडी हटाने के फैसले से धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके हिस्से की कोई सहूलियत उनसे वापस ली जा रही है। उम्मीद करें कि हज सब्सिडी के पैसों से सरकार मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की ऐसी ठोस व्यवस्था करेगी, जिससे गरीब लड़कियों को मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा। जहां तक हज का प्रश्न है, तो सब्सिडी वापस लेने के बाद भी सरकार को इस मामले से पूरी तरह अपने हाथ नहीं खींचने चाहिए। हज यात्रियों को अन्य स्तरों पर हर संभव सहायता देना उसका फर्ज है।

▪ जीने का सलीका

एक युवक था। वह बंदूक और तलवार चलाना सीख रहा था। इसलिए वह यदा-कदा जंगल जाकर खरगोश, लोमड़ी और पक्षियों आदि का शिकार करता। शिकार करते-करते उसे यह घमंड हो गया कि उसके जैसा निशानेबाज़ कोई नहीं है और न उसके जैसा कोई तलवार चलाने वाला। आगे चलकर वह इतना घमंडी हो गया कि किसी बड़े के प्रति शिष्टाचार भी भूल गया। उसके गाँव के बाहर कुटिया में एक संत रहते थे। वह एक दिन उनके पास पहुँचा। न उन्हें प्रणाम किया और न ही अपना परिचय दिया। सीधे उनके सामने पड़े आसन पर बैठ गया और कहने लगा, लोग बेकार में स्वर्ग-नरक में विश्वास करते हैं? संत ने उससे पूछा, तुम तलवार साथ में क्यों रखते हो? उसने कहा, मुझे सेना में भर्ती होना है, कर्नल बनना है।

इस पर संत ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग सेना में भर्ती किए जाते हैं? पहले अपनी शक्ल शीशे में जाकर देख लो। यह सुनते ही युवक ग़ुस्से में आ गया और उसने म्यान से तलवार निकाल ली। तब संत ने फिर कहा, वाह! तुम्हारी तलवार भी कैसी है? इससे तुम किसी भी बहादुर आदमी का सामना नहीं कर सकते, क्यों कि वीरों की तलवार की चमक कुछ और ही होती है।

फिर तो युवक गुस्से से आग-बबूला हो गया और संत को मारने के लिए झपटा। तब संत ने शांत स्वर से कहा, अब तुम्हारे लिए नरक का दरवाज़ा खुल गया।

यह सुनते ही युवक की अक्ल खुल गई और उसने तलवार म्यान में रख ली। अब वह सर झुककर संत के सामने खड़ा था और अपराधी जैसा भाव दिखा रहा था। इस पर संत ने कहा, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया।

▪ ज्ञान की परख

1. आंध्रप्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ कौनसे कमांडो मोर्चा संभालते हैं?

2. किस राज्यसभा सांद ने भाजपा से इस्तीफा दिया है?

3. वेस्टइंडीज में अपने पहले टेस्ट मैच में किस भारतीय कप्तान ने सेंचुरी बनाई है?

4. किस सांसद ने संसद का वीडियो पोस्ट किया है?

5. रजनीकांत की कौनसी फिल्म ने रिकार्ड कमाई की है?

1. ग्रेहाउंड कमांडो 2. नवजोत सिंह सिद्धू 3. विराट कोहली
4. आप पार्टी के सांसद भगवंत मान 5. कबाली

राजनीतिक शक्ति बनें किसान

अगर किसी कृषि प्रधान देश में कृषि और किसान ही संकट में आ जायें तो देश की दशा-दिशा का अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह बात दशकों से पाठ्य पुस्तकों में पढ़ायी जाती रही है, क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत तक आबादी जीवनयापन के लिए कृषि और उससे जुड़े काम-धंधों पर निर्भर रही है। इसलिए ग्रामीण भारत को ही असली भारत भी कहा गया। आजादी के बाद हमारे शासकों ने शहर केंद्रित औद्योगिकीकरण का विकास मॉडल चुना। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि गांवों में बसने वाली और जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर आबादी का प्रतिशत घटता गया है। नब्बे के दशक में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद से तो गांवों से शहरों की ओर पलायन की यह रफ्तार और भी तेज हुई है।

राजकुमार सिंह

ऐसा नहीं है कि शहरों और वहां केंद्रित विभिन्न तरह के उद्योग-धंधों ने ग्रामीणों के स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा दिये हैं। कड़वा सच तो यह है कि आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में सरकारी-गैर सरकारी नौकरी के लिए गांव से शहर जाने की प्रवृत्ति अब जीवनयापन के लिए किसी भी तरह की मेहनत-मजदूरी करने की मजबूरी में बदल गयी है। हर शहर के बाहरी, या अब अंदरूनी इलाकों में भी, जो तेजी से बढ़ती झुग्गी बस्तियां दिखायी पड़ती हैं, वे दरअसल इसी भारत महान के लाड़लों के बसेरे हैं। ये लोग शहर आते तो हैं बेहतर जीवन की आस में, पर पाते हैं हाशिये पर जैसे-तैसे घिसटती जिंदगी।

निश्चय ही इसके लिए शहरवासियों को दोष नहीं दिया जा सकता। अपनी जरूरत की मजबूरी में ही सही, शहरवासी तो इन्हें जीवनयापन का जरिया ही उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन देश के नीति-नियंता तो इनकी बदहाल जिंदगी के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। आजाद भारत के विकास का मॉडल हमारे हुक्मरानों को ही चुनना था। महात्मा गांधी ने आगाह भी किया था कि असली भारत गांव में बसता है और लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई गांव ही हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल और चौधरी चरण सिंह भी बताते रहे कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत-खलिहान से होकर गुजरता है। फिर भी हमारे हुक्मरानों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वायत्त और टिकाउ बना सकने वाले कुटीर उद्योगों के बजाय शहर केंद्रित विशाल औद्योगिकीकरण की राह चुनी। यह सही है कि उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं और बदलते विश्व परिदृश्य में उनके बिना दुनिया के साथ कदमताल भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी 20-30 प्रतिशत शहरी आबादी को ही ध्यान में रखकर भारत सरीखे विशाल और बहुलतावादी देश की विकास योजनाएं नहीं बनायी जा सकतीं। सत्ता अहमन्यता का पर्याय जो बन गयी है। तभी तो चौतरफा बदहाली-बर्बादी के बीच भी मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बन रहा है सरीखे आत्ममुग्ध नारे सुनायी पड़ते हैं।

वापस गांव और कृषि की ओर लौटते हैं। शहर की ओर बढ़ते पलायन के परिणामस्वरूप अब गांवों में 50 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा आबादी रह गयी है, पर सवा अरब से भी ज्यादा आबादी वाले भारत में यह संख्या कम है क्या? फिर संविधान तो हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। आजादी के 70 सालों में ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई अचानक ही चौड़ी नहीं हो गयी है। देश की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं की दशा-दिशा के चलते यह खाई लगातार बढ़ती गयी है। जाहिर है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार बढ़ रहे हैं तो बंटवारे के चलते कृषि भूमि और उससे होने वाली आय लगातार घट रही है। गांवों से बढ़ते पलायन के चलते शहरों के विस्तार और नये शहरों की बसावट की मजबूरी भी अंततः गांवों और कृषि भूमि को ही निगल रही है। फिर आजादी के 70 साल में भी गांवों तक रोजगार तो दूर, बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं का न पहुंच पाना भी युवाओं को मजबूर कर रहा है कि मृगतृष्णा के वशीभूत होकर ही सही, वे शहरों की ओर पलायन करें।

ऐसा नहीं है कि हमारे नीति-नियंता अपने विकास मॉडल के दुष्परिणामों का अनुमान नहीं लगा सकते थे, पर उन्होंने तो सामने आने पर भी इन विकृतियों का निदान करने की कोई कार्ययोजना नहीं बनायी। ये परिणाम बेहद स्वाभाविक थे। इसीलिए चौधरी चरण सिंह सरीखे जमीन से जुड़े राजनेता लगातार ग्रामीणों को कृषि से इतर वैकल्पिक रोजगारों के लिए अपने बच्चों को तैयार करने की सलाह देते रहे। बेशक यह काम आसान नहीं था, क्योंकि गांव में सुविधाएं नहीं थीं और शहर जाने का सामर्थ्य नहीं था। इसलिए सत्ताधीशों का इंडिया शाइन करता रहा और आम आदमी का भारत लगातार धुंधलाता रहा।

बेशक यह संकट सिर्फ कृषि का नहीं है, लेकिन गैर किसान ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था, और नतीजतन जीवनयापन भी कृषि के इर्द-गिर्द ही घूमता है। इसलिए कृषि का संकट अंततः पूरे ग्रामीण जीवन का ही संकट बन जाता है। निस्संदेह कृषि का संकट पुराना है, लेकिन अन्नदाता द्वारा आत्महत्या की खतरनाक प्रवृत्ति अपेक्षाकृत नयी है। निष्कर्ष पर पहुंचना तो जल्दबाजी होगी, पर इस गहन निष्पक्ष पर शोध की जरूरत निश्चय ही है कि कृषि प्रधान भारत में अन्नदाता किसानों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति 1991 में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद ही नजर आती है। दरअसल उदारीकरण और वैश्वीकरण का लाभ तो गांव और कृषि तक नहीं पहुंचा, उलटे उसकी दुश्वारियां लगातार बढ़ती गयीं।

निस्संदेह यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करने वाली है, लेकिन आश्चर्य की पराकाष्ठा देखिए कि किसान और कृषि इस देश के राजनीतिक एजेंडा पर चुनावी दांवपेच से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने किसान कर्ज माफी का झुनझुना बजाकर वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव जीत लिया था तो भाजपानीत राजग ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का झूठा वायदा कर 2014 में केंद्रीय सत्ता कब्जा ली। सच कड़वा होता है, और सच यह है कि दोनों ही बार किसान को छल के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज भी देश के विभिन्न भागों से अन्नदाता की आत्महत्या की खबरें नहीं आ रही होतीं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि संकट के इस काल में किसान राजनीति कहां गुम है? यों तो देश में किसान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से मानी जा सकती है, लेकिन स्वामी सहजानंद, चौधरी छोटूराम, चरण सिंह और देवीलाल से लेकर शरद जोशी-महेंद्र सिंह टिकैत तक किसान नेतृत्व की जो लंबी श्रृंखला रही है, उसके मद्देनजर तो किसान राजनीति का यह बांझपन और भी हैरान करने वाला है।

पराक्रमी विद्वान प्रो. जयनारायण पाण्डेय

कुछ यादगार पल लिख छोड़ें, इसी धुन में विचार आया कि जिन्दगानी की कुछ ऐसी मिसाल, ऐसे व्यक्तित्व का जिक्र करूँ, जिन पर कलम चलाने पर फक्र महसूस हो, सो प्रस्तुत है. `` सरकार समझती है कि पूंजी लगाकर पूजीपति देश पर बड़ा उपकार करता है. हमारा कहना है कि यह दौलत पूॅजीपति पैदा होने पर कहीं से बॉध कर नहीं लाया था. वह तो इसी दुनिया में उसने या उसके बाप दादों ने लाखों गरीबों का पेट काटकर बटोरा है और आज मजदूरों के श्रम की बदौलत पूॅजीपति देशभक्त बन गये. खाली पूॅजी से उत्पादन होता तो हमारे बिड़ला जी, टाटा, डालमियॉ आदि मजदूरों की हड़ताल की भूत से ना घबराते.

सुकुमार ठाकुर

पुण्यतिथि 20 जनवरी के अवसर पर विशेष

पूॅजी को तो श्रम चाहिए ही, जो हजारों लाखों मजदूरों और मजलूमों के खून पसीने से आता है. '' वर्तमान में भी प्रासंगिक उपरोक्त पंक्तियॉ सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र ' जनमत ' के अग्रलेख में संपादक द्वारा अबसे लगभग 68 वर्षों पूर्व लिखी गयी थी. बात करते हैं, अंचल के प्रख्यात शिक्षाशास्त्री की जिनका जीवन ही शिक्षा और प्रशिक्षण की पाठशाला है. जिस शख्सियत पर कुछ लिख पढ़ सकने का हिमाकत कर सकता हूं, वो हैं ? प्रो. जयनारायण पाण्डेय. मुझे '' सर '' का सानिध्य प्राप्त हुआ 1960 में, ये वही साल हैं जब जगदलपुर डिग्री कॉलेज आरंभ हुआ था. बस्तर में शैक्षणिक गतिविधियों को विस्तार देने के उद्देश्य से जगदलपुर डिग्री कॉलेज मे चुने हुए महाविद्यालयीन शिक्षकों की पदस्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई थी.

उस बैच के सभी छात्रों के मन में बड़ा ही कौतुहल था '' सर '' जयनारायण पाण्डेय जी को लेकर अंचल व प्रदेश के नामचीन शिक्षाशास्त्री राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी व हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान वैचारिक क्रान्ति के प्रवर्तक, मुक्ति संग्राम काल की अग्रिम पंक्ति के योद्धा, राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी कॉमरेड की छवि रखने वाले, मर्जर मूव्हमेंट को अंचल में नेतृत्व प्रदान करने वाले जनमत अखबार के संपादक, शालेय शिक्षा से महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान सदैव मेधावी रहे प्रो. पाण्डेय की ख्याति सी.पी. प्रदेश के दौरान ही विदर्भ महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के बौद्धिक समाज में तथा राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के क्षितिज पर दैदीप्यमान थी.

हाई टेक्नालॉजी कम्प्यूटर युग को हम सबने विगत पैंतीस वर्षों से भली-भॉति जाना है. अपने आप में कम्प्यूटर सा ज्ञान संकलित रखने वाले प्रो. जयनारायण पाण्डेय जी द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्य परक दलीलें, विभिन्न एकेडेमिक विषयों राजनैतिक व सामाजिक विषयों पर उनके गंभीर अध्ययन, को दर्शाता था. '' सर '' के भाषण के संदर्भ में हम लोगों ने सुन रखा था कि अमेरिकी राजदूत ऐलन तथा पट्टाभि सीतारमैय्या जैसों के अंग्रेजी के भाषण का भाषा रूपान्तरण हिन्दी में मंच पर ही कर दिया था, उनके हिन्दी भाषण को मूलतः अंग्रेजी के भाषण से अधिक प्रशस्ति प्राप्त हुई थी. '' सर '' के द्वारा लिखित प्रमुख '' राजनीतिक विचारकों की चिन्तनधारा '' के साथ ही साथ समसामयिक निबंध, समीक्षायें कविताओं का संग्रह विशेषतः अंत, गुनाह खाने में, ज्योत्सना, बुझती ज्वाला के अंतिम क्षण, हिन्द का तारा चमकता जायेगा, आहुति का कविता पाठ जब-जब पाण्डेय सर ने कॉलेज मंच पर किया वशीभूत छात्र, अध्यापक वर्ग जो आज मौजूद है, उस वशीकरण मंत्र वाली भाषा, ओजस्वी वाणी शब्द विन्यास, मर्म और उस लहजे को भूल नहीं सके है.

पाण्डेय सर के विषय में मुझे एक बात और पता चली थी कि, जगदलपुर शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ होने के पूर्व जयनारायण पाण्डेय सर रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में लगभग तीन वर्षों तक अध्यापन कार्य संपादित करते रहे. इस दौरान उनके साथ दर्शनशास्त्र में बतौर व्याख्याता रजनीश भी कार्यरत थे, उस समय श्री रजनीश आचार्य रजनीश की ख्याति नहीं रखते थे. रजनीश जी प्रायः पाण्डेय सर से विभिन्न गंभीर विषयों पर चर्चा करते थे, ये चर्चा प्रायः '' डिबेट '' का रूप ले लिया करती थी. समकालिन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया था, कि पाण्डेय जी हमेशा अपने अकाट्य तर्कों से श्री रजनीश को ना सिर्फ अवगत कराते थे, उन पर भारी पड़ते थे. प्रोफेसर जयनारायण पाण्डेय राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक रहे, मैं उस दौरान बी.एस.सी. गणित संकाय का छात्र था. सर की ओजस्वी वाणी, धारा प्रवाह अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा विषय पारंगकता से वशीभूत हो, मैं प्रायः उनकी पॉलीटिकल साईन्स की क्लास भी अटेण्ड करता था. सर ये जानते हुए कि मैं गणित संकाय का छात्र हूं, मुझे व्याख्यान को सुनने का अवसर दिया करते थे. जगदलपुर महाविद्यालय के हर संकाय के शिक्षक एवम् छात्र प्रो. पाण्डेय की '' पराक्रमी विद्वान की विद्वता '' का कायल था. '' सर '' का विषय परक गूढ़ अध्ययन उन्हे ना सिर्फ शिक्षा, वैचारिक उत्कृष्टता के उच्चतम स्थान पर प्रतिस्थापित करता था, बल्कि उनकी वैचारिक उर्जा की वजह से पूरे प्रदेश में उन्हें ख्यातिनाम बना चुका था. '' सर '' सफेद कुर्ता पायजामा अथवा धोती पहनकर ही कॉलेज आते थे बेहद सादगी भरे अंदाज में, पर अपने अकाट्य वैचारिक तर्कों से बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री विद्वानों को पलभर में ही धराशयी कर देते थे. इसीलिये मैने सर की विद्वता के संदर्भ में अलंकार रूपी शब्द '' पराक्रमी विद्वान की विद्वता '' का उल्लेख किया है.

अपने शैक्षणिक काल और सामाजिक जीवन में कई आलातरीन किरदार मैने देखे और परखे हैं, व्यक्तित्व की विधा जो मैं सिर्फ प्रो. पाण्डेय में ही देख सका, वो थी असीमित क्रांतिकारी सोच, विद्वता का कुबेर अपने आप में संचित रखने वाला मध्यमवर्गीय, समाजवादी व्यक्ति किस तरह से अपनी सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सीमित हो जाता है, इसका उदाहरण है, प्रो. जयनारायण पाण्डेय का व्यक्तित्व और उनकी मात्र 39 वर्षो की आयु तक धरा में बितायी हुई शताब्दी तक याद रहने वाली जीवन्त जिन्दगानी.

काश ! पाण्डेय जी को उनके जीवनकाल में महत्व मिलता, तो प्रखर समाजवादी कॉमरेड प्रो. पाण्डेय देश की व्यवस्था सिकती हुई रोटी जो कि तवे पर पलट-पलट कर ठीक कर ली जाती है, ठीक उसी तरह देश की व्यवस्था सीधी पटरी पर लाकर ही हम सबसे विदा लेते!

मोबाइल इंटरनेट दरों को लेकर जंग तेज

WEB कॉर्नर

मोबाइल इंटरनेट की दरों को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच जंग तेज हो गई है। बीते हफ्ते डाटा दरें घटाने के बाद आइडिया सेलुलर ने फिर से मोबाइल इंटरनेट दरों में कटौती का एलान कर दिया है। आदित्य बिड़ला समूह की इस कंपनी ने अपने सभी सर्किलों में 4जी व 3जी डाटा की दरों में 67 फीसद तक की कमी की है। कंपनी ने यह कदम प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल को टक्कर देने और रिलायंस जियो के खतरे को भांपते हुए उठाया है। बीते दिन एयरटेल ने डाटा दरें 67 फीसद घटाने की घोषणा की थी। आइडिया की दरों में ताजा कटौती का फायदा इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा। अब कंपनी के प्रीपेड ग्राहक 10 जीबी का 4जी व 3जी मोबाइल इंटरनेट पैक 990 रुपये और पांच जीबी का पैक 649 रुपये में खरीद सकेंगे। दो जीबी का डाटा पैक अब 449 रुपये की बजाय 349 रुपये में मिलेगा। पोस्टपेड ग्राहकों के लिए भी जल्द ही घटी दरों का एलान किया जाएगा। पिछले हफ्ते आइडिया ने एक जीबी से कम डाटा उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए दरें 45 फीसद तक घटाई थीं। बीते दिन की घोषणा के बाद पहले वाली कीमत पर एयरटेल के नए 4जी व 3जी मासिक पैक पर 40–67 फीसद ज्यादा डाटा मिलने लगा है। छोटे (सैशे) पैक वाली श्रेणी में 32 से 48 फीसद अधिक डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे।

पिछले हफ्ते मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने दावा किया था कि कॉमर्शियल लांच से पहले ही इसके 4जी नेटवर्क से 15 लाख ग्राहक जुड़ चुके हैं। जियो 2,999 रुपये के अपने स्मार्टफोन लाइफ के साथ 90 दिनों की असीमित 4जी मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा मुफ्त दे रही है।

यही नहीं, कंपनी ने दावा किया है कि वह मौजूदा रफ्तार के मुकाबले 40 से 80 गुना ज्यादा ब्रॉडबैंड स्पीड देगी। जानकारों का कहना है कि जियो के आने से मोबाइल इंटरनेट को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच जंग तेज होगी। ग्राहकों को इसका फायदा सस्ती डाटा दरों के रूप में मिलेगा।

दूरसंचार कंपनियों के शेयर गिरे

टेलीकॉम कंपनियों के बीच कीमतों की जंग को देखते हुए सोमवार को इनके शेयर गिरावट का शिकार हुए। बीएसई पर आइडिया का शेयर 6.5 फीसद का गोता लगाकर 103.90 रुपये पर आ गया। भारती एयरटेल का शेयर भी चार फीसद लुढ़क 363.45 रुपये पर बंद हुआ।

▪ जरा इनकी भी सुनिए

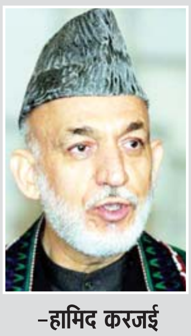

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित हाफिज सईद के खिलाफ बहुत सारे सुबूत हैं।

–हामिद करजई
पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान

यह मामला तभी देखेंगे, जब रजिस्ट्री इस याचिका को सुनवाई के लिए लगाएगा।

–जस्टिस दीपक मिश्रा
प्रधान न्यायाधीश

ट्विट ट्विट

निकलॉज–सैमुअल गुग्गर स्विट्ज़रलैंड में पहले भारतवंशी सांसद हैं। 48 साल पहले एक स्विस दंपती ने उन्हें गोद लिया था। निकलॉज पिछले सप्ताह प्रवासी भारतीय सांसदों के सम्मेलन हिस्सा लेने यहां आए थे।

–निकलॉज–सैमुअल

चेन्नई के आईआईटी अनूठे शोध पार्क देखने के बाद बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुसंधान के क्षेत्र में काफी कमी है। हम बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं।

–प्रकाश जावड़ेकर